बिहार की राजनीति में जाति आधारित राजनीतिक दलों का अस्तित्व एवं संभावना (1999- 2022)

वाई०बी०एन० युनिवर्सिटी, राजाउलातु, नामकुम, राँची
के समाज विज्ञान संकाय (राजनीति विज्ञान विभाग)
में पीएच०डी० उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध–प्रस्ताव

Approved
HOD
POLITICAL SCIENCE
YBN UNIVERSITY, RANCHI-10

Dr. Ruby Kumari
Supervisor, Dept. of Political Science
YBN University Ranchi-834010

शोध–निर्देशिका
डॉ० रूबी कुमारी
असिस्टेंट प्रोफेसर,
राजनीति विज्ञान विभाग
वाई०बी०एन० विश्वविद्यालय, राँची
(झारखण्ड)

शोधार्थी
प्रिंस कुमार
Enrollment No. : YBNU2000493
राजनीति विज्ञान विभाग
वाई०बी०एन० विश्वविद्यालय, राँची
(झारखण्ड)

वाई०बी०एन० विश्वविद्यालय, राँची (झारखण्ड)

2023

Scanned with OKEN Scanner

बिहार की राजनीति में जाति आधारित राजनीतिक दलों का अस्तित्व एवं संभावना

(1999–2022)

भारत में जाति व्यवस्था भारतीय सामाजिक व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय संविधान जाति–भेद को अस्वीकृत करके जातिविहीन समाज व्यवस्था पर जोर देता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कई नेताओं और संविधान निर्माताओं को यह उम्मीद थी कि लोकतांत्रिक शासन और आधुनिकता जाति जैसी संस्थाओं को कमजोर कर देगी। लेकिन भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में हितों के संघत्व और अभिव्यक्ति के लिए जाति की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है।

जाति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द जात से हुआ है जिसका अर्थ है– "जन्म लेना अथवा अस्तित्व में आना। जाति की पहचान जन्म के आधार पर किया जाता है तथा यह विरासत में प्राप्त होती है जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वह पिता के जाति को ग्रहण करता है।

जाति राजनीतिक प्रक्रियाओं में जाति एक केन्द्रीय क्रियात्मक तत्व बन गई है। हालांकि जाति और राजनीति का संबंध स्थिर नहीं रहता समयानुसार परिवर्तित होता रहता है।

जाति आधारित राजनीति दलों के अस्तित्व और संभावनाओं को समझने के लिए बहुत से विद्वानों के द्वारा महत्वपूर्ण वक्तव्य को इस प्रकार देख जा सकता है–

- मजूमदार और मदन के अनुसार– "जाति एक बंद वर्ग है।"
- कूले के अनुसार– "जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तो हम इसे जाति कहते हैं।"
- केल्कर के अनुसार– "जाति दो विशेषताओं वाला सामाजिक समूह है– (i) सदस्यता उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित रहती है, जो सदस्यों से उत्पन्न होते है एवं इस प्रकार उत्पन्न सभी व्यक्ति उसमें शामिल रहते है एवं (ii) सदस्यों पर एक

Scanned with OKEN Scanner

अनुलंधनीय सामाजिक नियम द्वारा जाति के बाहर विवाह करने पर प्रतिबंध रहता है।

उपयुक्त परिभाषाओं के द्वारा संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि जाति वंशानुरागी व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो परम्परागत व्यवसाय करते है तथा जातीय नियमों और निषेधों का पालन करते हैं।

- रेने तथा केन्डेल के अनुसार– "राजनीतिक दल संगठित स्वायत्त समूह है जो सरकार की नीतियों एवं कर्मचारियों पर अन्ततः नियंत्रण प्राप्त करने की आशा में चुनाव में उम्मीदवारों का नामांकन करते और चुनाव लड़ते हैं।
- मैकाइवर के अनुसार– राजनीतिक दल एक ऐसा समुदाय है जो किसी ऐसे सिद्धांत अथवा नीति के समर्थन के लिए संगठित हुआ हो जिसे वह वैधानिक साधनों से सरकार का आधार बनाना चाहता है।

इस प्रकार से हम जाति और राजनीतिक दल समाज परिवर्तन की प्रक्रिया को जन्म देता है।

- रजनी कोठारी के अनुसार– "जाति और लोकतांत्रिक राजनीति की अन्योन्यक्रिया ने समाज परिवर्तन की प्रक्रिया को जन्म दिया।"

"भारतीय संविधान जाति भेद को अस्वीकृत करके जातिविहीन समाज के लिए प्रतिबद्ध है।"

- कार्ल मार्क्स के अनुसार– धर्म के मानव के लिए अफीम है जबकि इस अवधारणा को डॉ० अम्बेडकर ने विरोध किया तथा उन्होंने बताया कि धर्म सामाजिक जीवन में प्रभाव या बल के रूप में हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सम्मिलित है तथा उसके चरित्र क्रिया या प्रतिक्रिया रूचि और परिष्कार करती है।

उपयुक्त सभी महत्वपूर्ण वक्तव्यों के द्वारा जाति, राजनीतिक दल और जाति और राजनीति के मध्य संबंध को समझना आसान है। जाति भारतीय राजनीति को बहुत हद तक प्रभावित करती दिखाई पड़ती है।

बिहार में सभी धर्मों को मानने वाले लोग तथा सभी धर्मों को वैश्विक केन्द्र बिहार र हा है। मनु आधारित जाति व्यवस्था बिहार में विद्यमान है। बिहार के राजनीति में आरम्भिक चुनाव से ही स्वर्ण जातियों का वर्चस्व रहा है। शिक्षा, आरक्षण, राजनीति,

Scanned with OKEN Scanner

जागरूकता, जाति ध्रुवीकरण आदि के कारण सम्भवतः पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों का बिहार के राजनीति में प्रवेश मिला।

बिहार में जातिकरण के पश्चात राजनीति में जातियों के प्रभाव का विभाजन औपनिवैशिक दौर में, 1947 से 1967 तक और 1967 से 1990 तक और 1990 से वर्तमान तक जातियों का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। अंग्रेजों के आगमन से पहले ऊँची हिन्दू जातियाँ (ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ) और कुछ मुस्लिम जातियां ही समाज में अभिजन वर्ग के रूप में थी इसका मुख्य कारण है कि इन्हें समाज में प्रतिष्ठा भी प्राप्त थी और आर्थिक संसाधनों पर भी इनका अधिपत्य था। 1793 में अंग्रेजों ने स्थायी बन्दोवस्त अधिनियम के इस नये प्रकार दिया। भूमि स्वामित्व की इस व्यवस्था में जमींदार, भूमिपति, जोतदार निचले स्तर के खेतिहार मजदूर थे। इस व्यवस्था में जमींदार अपने से निचले तबके का शोषण करते थे। यह पूरी व्यवस्था शोषण पर आधारित थी। यह एक जटिल और स्तरीकृत व्यवस्था थी।

वर्तमान परिदृश्य में बिहार में धर्म एवं जाति आधारित नेता जैसे पासवानों या अनुसूचित जातियों के नेता रामविलास पासवान, कोइरी–कुर्मी नेता नीतिश कुमार, यादवों और मुस्लिमों के नेता लालू प्रसाद यादव आदि गर्व से शासन व्यवस्था का सक्रिय सदस्य है। बिहार में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों हमेशा विकास के नाम पर चुनाव लड़ते हैं जबकि वास्तविकता में यह जाति समीकरण एवं धर्म तुष्टीकरण पर आधारित होता है तथा चुनाव परिणाम में पश्चात् भी मंत्रिमण्डल के निर्माण में इन तत्वों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है जो एक अच्छे लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है।

वर्ष 2010 में बिहार विधानसभा चुनाव में नीतिश कुमार के नेतृत्व में राज्य के राजग में जनता दल (यू) और समय नीतिश कुमार ने प्रसिद्ध पत्रकार अरूण कुमार से बात करते हुए ऐसे टिप्पणी की जो बिहार की राजनीति में जातिवाद की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है।

नीतिश कुमार :–

"अपने समाज के श्रेष्ठ और उत्कृष्ट के तमाम बड़े दलों के बावजूद इस चुनाव के परिणाम जातिवाद से बुरी तरह प्रभारी रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि कुछ लोगों ने जाति से ऊपर उठकर मतदान किया किन्तु जातिवाद ने निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जातिवाद जितना हमारे लिए प्रतिकूल हो सकता है।

Scanned with OKEN Scanner

उतना अनुकूल भी हो सकता है क्योंकि कुछ जातिया एकमत होकर सामूहिक रूप से किसी राजनीतिक दल के प्रति प्रतिबद्ध हो सकती है। उनके लिए मतदान कर सकते हैं जैसे कि पहले चुनावों में यादव जाति ने राजग के लिए किया था। उन्होंने कहा हमें उग्र जातिवादी ताकतों से एक और लड़ाई लड़नी होगी– विशेषकर सभी जातियों में उपस्थिति उग्र जातिवादी ताकतों से।"

उपयुक्त बातों से हमें यह भली–भांति पता चलता है कि बिहार की राजनीति जातियत के प्रभाव से बहुत अधिक प्रभावित है इसके कुछ अनुकूल प्रभाव भी है तो कुछ प्रतिकूल प्रभाव। अतः बिहार की राजनीति में जातियता का अस्तित्व और संभावना निरंतर परिवर्तन का अध्ययन कर हम इसके प्रभाव को अनुकूल करने का प्रयास कर सकते हैं।

अध्ययन क्षेत्र :–

हमारे शोध का अध्ययन क्षेत्र बिहार राज्य है। बिहार की राजनीति में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण देखी गई है। साथ ही जाति और राजनीति के आपसी संबंधों का सैद्धांतिक विश्लेषण भी किया गया है। अध्ययन की निरंतरता के लिए इस शोध में बिहार की राजनीति में जाति आधारित राजनीतिक दलों का अस्तित्व एवं संभावनाओं के आकलन के लिए 1999 से वर्तमान समय तक में जाति की भूमिका और उसके प्रभावों के कारण होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करने का प्रयास करेगा।

जैसा कि हम सब यह जानते हैं कि सन् 2000 में बिहार के विभाजन के पश्चात् झारखण्ड के नाम से एक नया राज्य बना। इसलिए इस अध्ययन में 2000 के विधानसभा चुनावों तक का विश्लेषण और उसके बाद शेष नये बिहार की राजनीति का विश्लेषण करने का प्रयास किया जाएगा। विभाजन के पूर्व बिहार के विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 324 थी झारखण्ड राज्य के निर्माण के बाद इसमें 81 सदस्य कम हो गए। और बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या 343 हो गई। इसी प्रकार लोकसभा में विभाजन के पूर्व बिहार के सदस्य संख्या 54 थी जो 40 हो गई। वर्तमान में 14 लोकसभा क्षेत्र झारखण्ड में है। बिहार में 22 राज्यसभा सदस्य चुने जाते थे जो अब संख्या में 16 रह गई है।

Scanned with OKEN Scanner

बिहार विभाजन के पहले बिहार में ऊँची और पिछड़ी जातियाँ राज्य की कुल जनसंख्या का 19.3 फीसदी थी यादव 4.6 फीसदी और बनिया 0.6 फीसदी थे कोयरी 4.1 और कुर्मी 3.6 फीसदी थे। बिहार विभाजन के पूर्व राज्य की जनसंख्या में निम्न पिछड़ी जातियों में बढ़ई, धानुक, हजाम, कहार, तेली, कुम्हार आदि जातियों को शामिल किया गया है। विभाजन के पूर्व बिहार में अनुसूचित जातियाँ 14 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियाँ 9.1 फीसदी थी।

बिहार विभाजन के पश्चात बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की संख्या में कमी आई क्योंकि राज्य के जिन क्षेत्रों को झारखण्ड राज्य का निर्माण किया गया वे मुख्यतः आदिवासी बहुल क्षेत्र था।

शोध–कार्य का उद्देश्य :–

इस अध्ययन का उद्देश्य बिहार के विशेष संदर्भ में जाति की राजनीति के विभिन्न आयामों का विश्लेषण करना है। भारतीय राजनीति में जाति सामाजिक संस्थाओं पर जाति का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। इस शोध में बिहार राज्य में जाति पर आधारित राजनीतिक दलों के अस्तित्व और समाज पर, लोकतंत्र पर, भारतीय सामाजिक व्यवस्थाओं पर पड़ने वाले प्रभावों, कारणों तथा उनसे होने वाले दुष्प्रभावों का अध्ययन करना ही इस शोध का मुख्य उद्देश्य होगा। साथ ही राजनीतिक दलों पर बढ़ते जाति के प्रभावों को कम करने तथा सही दिशा में इसके रोकथाम को सरकार और संविधान द्वारा निर्मित कानूनों के माध्यम से परिवर्तन के उद्देश्य से अध्ययन करना तथा जाति में राजनीतिक अस्तित्व और संभावनाओं के संबंध में जानना ही इस अध्ययन का उद्देश्य होगा।

शोध–कार्य का महत्व एवं प्रासंगिकता :–

प्रस्तुत शोध जाति पर आधारित राजनीति दलों से संबंधित जितने भी अध्ययन हुए है उनकी विवेचना से स्पष्ट है कि राजनीतिक दलों में जातियता के आधार पर बढ़ते प्रभाव एवं स्थिति से संबंधित अध्ययनों का अभाव है। अतः बिहार की राजनीति को अच्छे से अध्ययन करने के लिए जाति पर आधारित राजनीतिक दलों का अध्ययन करना आवश्यक प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार वर्तमान समय में बिहार की राजनीतिक

Scanned with OKEN Scanner

सामाजिक स्थिति को ध्यान पर रखते हुए वर्तमान शोध–कार्य बिहार जिले के राजनीतिक दलों पर जातियता के प्रभाव का अध्ययन करेगा। यह शोध उसी दिशा में एक प्रभाव है।

बिहार की राजनीतिक स्थिति में नीतियों, वैधानिक प्रावधानों के द्वारा कई सुधार हुए है लेकिन जातीय के प्रभाव से बिहार अब भी जकड़ा हुआ प्रतीत होता है। बिहार में राजनीतिक दलों का गठन ज्यादातर जाति पर आधारित होता है जिसके अन्तर्गत अनेक समूह गठबंधन कर अपने जाति पर आधारित राजनीतिक दलों को प्रभावित करते हैं।

बिहार राजनीतिक सामाजिक स्थिति एवं समस्याओं को समझने उपरान्त ही राजनीतिक दलों में बढ़ती जातियता के प्रभाव का मूल्यांकन एवं आकलन करना होगा। स्वाभाविक रूप में वर्तमान समय में ऐसे शोध महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक होंगे।

उपलब्ध साहित्य की समीक्षा :–

बी० डी० सुदीप्त कविराज ने अपनी पुस्तक 'पॉलिटिक्स इन इंडिया' में भारतीय से विधायक में जातिविहीन समाज से जुड़े तथ्यों की विवेचना की है साथ अपनी पुस्तक में भारतीय संविधान में जाति पर आधारित कानूनों के विषय में जानकारी प्रदान की है।

रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक 'भारत में राजनीति कल और आज' में भारतीय राजनीति में जाति के प्रभावों और कारणों की विशद् चर्चा की है साथ ही भारतीय राजनीति और जाति के अन्योन्यती से समाज में होने वाले पविर्तनों की बात कही है।

श्री संजय कुमार ने अपनी पुस्तक 'बिहार की चुनावी राजनीति जाति वर्ग की समीकरण' पुस्तक में बिहार के राजनीति के विषय में विशद् व्याख्या की है। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति समय से वर्तमान परिदृश्य में बिहार के बदलती राजनीति का चित्रण उन्होंने बहुत ही विस्तृत रूप से किया है।

कुमार दिनेश ने अपनी पुस्तक 'गठबंधन राजनीति' में बिहार के राजनीतिक चित्रपट पर तात्कालिक परिस्थितियों और घटनाओं को बड़ी बेबाकी से प्रतिबिंबित किया है। बिहार की अवसरवादी राजनीति का उल्लेख किया है और बताया

Scanned with OKEN Scanner

है कि सार्वजनिक जीवन को आंदोलित करनेवाले मुद्दों के बावजूद बिहार में जातीय समीकरण बहुत ही मजबूत स्थिति में है।

श्री कमल चयन चौबे ने अपनी पुस्तक जातियों का राजनीतिकरण' में बिहरी में पिछड़ी जातियों के उभार की दास्तान को विस्तृत रूप से उल्लेख किया है, उन्होंने अपनी पुस्तक में विभाजन से पहले बिहार में विभिनन जातियों और समूहों की जनसंख्या, राजनीतिक दलों की स्थिति की विशद् व्याख्या की है।

जे० एस० गुरैय ने अपनी पुस्तक 'कास्ट एण्ड रेस इन इंडिया' पुस्तक में जाति व्यवस्था की विशेषताओं प्रकृति, उत्पति के कारणों के विषय में बताया है।

सुजाता सोनी ने अपनी पुस्तक 'राजनीति कोश' में आज की बदलती हुई सामाजिक व्यवस्था और जटिल वातावरण को बताया है।

उपयुक्त सभी पुस्तकें भारत की राजनीति और बिहार की राजनीति में जातियता के प्रभाव, कारणों, वैधानिक प्रावधानों, सरकारी कार्यक्रमों, योजनाओं के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। किन्तु ये पुस्तकें जातीयता के प्रभाव का एकपक्षीय अध्ययन करता है। भारत एक सामाजिक और राजनीतिक समानता वाला देश है। अतः यह की जाति आधारित समाज का राजनीतिक और सामाजिक परिवेश एवं मूल्यों में भारतीय जनता के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका अध्ययन किए बिना जाति प्रथा की वास्तविक स्थिति उनके समस्याओं एवं प्रभावों की समुचित जानकारी नहीं हो सकती है।

अर्न्तनिहित शोध प्रश्न :—

1. बिहार की राजनीति का इतिहास क्या है ?
2. बिहार की राजनीति में जाति की भूमिका क्या बिहार में जाति पर आधारित राजनीतिक दलों कौन से है?
3. वर्तमान में बिहार राजनीति का केन्द्र राजनीति पर क्या प्रभाव हो रहा है ?

Scanned with OKEN Scanner

शोध पद्धति :–

प्रस्तावित शोध–प्रबंध में बिहार जिले के ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि अध्ययन के लिए ऐतिहासिक पद्धति का सहाज लिया जाएगा तथा भारतीय राजनीति में जाति के प्रभाव के अध्ययन के लिए विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए आँकड़ों एवं तथ्यों का संकलन कर उनका विश्लेषण किया जाएगा। संक्षेप में यह अध्ययन अतीत के अनुभव, वर्तमान प्रचलन तथा भावी दिशा संकेतों का निष्कर्ष होगा।

इस शोध के प्रबंध को तैयार करने में दो स्रोतों प्राथमिक और द्वितीयक से प्राप्त सामग्री तथा तथ्यों की प्रयोग किया जाएगा। द्वितीयक स्रोतों से लेखकों की रचनाओं शोध पत्रों तथा काउंसिल के पत्रिंका से संग्रहित की जायेगी।

इस प्रकार प्रस्तावित शोध की पद्धति ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक और आनुभाविक होगी।

प्रस्तावित अध्यायीकरण :–

प्रथम अध्याय : भूमिका

द्वितीय अध्याय: बिहार के राजनीतिक दलों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

तृतीय अध्याय : बिहार में जाति पर आधारित राजनीतिक दलों की बढ़ती सक्रियता

चतुर्थ अध्याय : 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार के विभिन्न राजनीतिक दलों की दशा एवं दिशा

पंचम अध्याय : बिहार की राजनीति में जाति आधारित राजनीतिक दलों का अस्तित्व एवं संभावना (1990–2022) तक

निष्कर्ष :

परिशिष्ट : पुस्तकें एवं पत्र–पत्रिकाएं तथा अन्य सामग्री

Scanned with OKEN Scanner

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. सुदीप्त, कविराज (1997). इंट्रोडक्शन संकलित सुदीप्त कविराज पॉलिटिक्स इन इंडिया. दिल्ली : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
2. कोठारी, रजनी (2006). भारत में राजनीति : कल और आज. दिल्ली : वाणी प्रकाशन.
3. अम्बेडकर और मनुवादी विश्लेषण. दिल्ली : ज्ञान पब्लिशिंग हाउस.
4. कुमार, संजय (1990–2013). बिहार की चुनावी राजनीति जाति वर्ग का समीकरण.
5. कुमार, दिनेश. गठबंधन की राजनीति. प्रभात प्रकाशन.
6. चौबे, कमल चयन (2008). जातियों का राजनीतिक. नई दिल्ली : वाणी प्रकाशन.
7. गुरैश, जे० एस०. कास्ट एण्ड रेस इन इण्डियाँ. मुम्बई : पॉपुलर प्रकाशन प्रा०लि०.
8. सोनी, सुजाता (2008). राजनीति कोश. एवरेस्ट पब्लिशिंग कम्पनी.
9. https://www.kailasheducation.com/2021.ry/jati arth-Paribhasha-vishestha html
10. भटनागर, एस० (1978). रूरल लोकल गवर्नमेंट इन इण्डिया. नई दिल्ली : लाइफ एण्ड लाइट पब्लिशर्स.
11. शर्मा, मुकेश (2002). पंचायती राज सिस्टम एण्ड एमपॉवरमेंट. जयपुर : सुरभि पब्लिकेशन्स.
12. सिंह, साहिब एवं सुरिन्द्र सिंह. लोकल गवर्नमेंट इन इण्डिया. नई दिल्ली ' एकेडमिक पब्लिशिंग कम्पनी.
13. सिवान्ना, एन० (1990). पंचायती राज रिफॉर्म एण्ड रूरल डवलपमेंट. इलाहाबाद : चुग पब्लिकेशन्स.
14. श्रीवास्तव, अरुण (1994). भारत में पंचायती राज. जयपुर : रावत पब्लिशर्स.

Scanned with OKEN Scanner